कम्प्यूटर शिक्षा

1910. **श्री ईश दत्त यादव:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कम्प्यूटर शिक्षा को प्रोत्साहन देने हेतु गैर-सरकारी संस्थाओं की सहायता लेने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा कम्प्यूटर शिक्षा के क्षेत्र में विकास हेतु क्या-क्या प्रयास किए गए हैं और इस संबंध में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) में राज्य मंत्री (डा० कृपासिंधु भोई): (क) और (ख) स्कूलों में कम्प्यूटर साक्षरता और अध्ययन (क्लास) नामक केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना इस समय सभी राज्यों में कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत हार्डवेयर की खरीद तथा हार्डवेयर के अनुरक्षण के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को कार्य में लगाने, शिक्षकों को प्रशिक्षित करने, आदि के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान प्रदान किए जाते हैं। इस योजना के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार कुछ राज्यों ने निजी कार्यान्वयन एजेंसियों को इस कार्य में लगाया है।

(ग) कम्प्यूटर शिक्षा के क्षेत्र में सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का संक्षिप्त रूप निम्न प्रकार हो सकता है:

(i) उपर्युक्त योजना के अंतर्गत, 7274 माध्यमिक/ उच्चत्तर माध्यमिक स्कूलों को कम्प्यूटर हार्डवेयर खरीदने तथा कार्यान्वयन एजेंसियों की कार्य में लगाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

(ii) इलैक्ट्रोनिकी विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजना के अंतर्गत, गैर औपचारिक षेत्र की 613 संस्थाओं/संगठनों को कम्प्यूटर पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए प्रत्यायन प्रदान किया गया है।

औपचारिक क्षेत्र में, इलैक्ट्रोनिकी विभाग ने कम्प्यूटर जनशक्ति विकसित करने के उद्देश्य से 303 संस्थाओं में कार्यक्रमों की सहायता प्रदान की है।

(iii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कम्प्यूटर हार्डवेयर खरीदने तथा उनके रख-रखाव के लिए 114 विश्वविद्यालयों तथा 1781 कालेजों को वित्तीय सहायता प्रदान की है। आयोग 31 विश्वविद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा में 88 पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए सहायता भी प्रदान की है।

Reservation in Professional courses in Delhi University

1911. SHRI NAGMANI: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to a news-report which appeared in the "Times of India" during 1st week of November, 1995 under the caption "No quota in New Management Course in Delhi University";

(b) if so, the details in this regard;

(c) the professional courses in Delhi University where reservations are not provided to SC/ST candidates; and

(d) the corrective measures proposed to be taken to ensure strict compliance of Government's directions provided for reservations in admissions for SC/ST in the Universty?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF EDUCATION AND DEPARTMENT OF CULTURE (KUMARI SELJA) (a) Yes, Sir.

(b) Univesity of Delhi has informed that four SC/ST candidates have been offered admission to Master of International Business and Master of Human Resource & Organisational Development Courses conducted by the Faculty of Commerce and Business of the University. The University has also stated that these students have been given special consideration as their marks in the Entrance Test were much below the marks obtained by the last general category candidates offered admission to these courses.

(c) and (d) According to the policy of

the Government, as reiterated by the University Grants Commission (UGC) from time to time, the Central Universities are required to provide 15% and 7 1/2% reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes respectively in admission to all courses. The following steps have been taken by the UGC to ensure implementation of reservation policy by the Central Universities:

(i) SC/ST Cells have been established in the Central Universities to safeguard interests of SC/ST candidates.

(ii) A Monitoring Committee has been set up to review, inter-alia, the progress made by the Universities in the matter of admission of students belonging to SC/STs in all courses offered by different Universities and to suggest measures for effective implementation of reservation policy.

(iii) The Commission has been circulating guidelines from time to time advising the Universities to adhere to the Government policy in this regard.

Need for Technical and Management Institutes

1912. SHRI K.M. KHAN: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn towards a pressing a need for a greater number of technical management education institutes in the country;

(b) whether such institutes will meet the wide demand for skilled professionals in commerce and industry in the current economic scenario;

(c) whether Government propose to take some steps in this regard; and

(d) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF EDUCATION AND DEPARTMENT OF CULTURE) (KUMARI SELJA): (a) to (d) The All India Council for Technical Education (AICTE) is a statutory authority for ensuring qualitative and quantitative growth of technical and management education in the country. The Council through its scheme of National Technical Manpower Information System (NTMIS) prepares up-to-date and meaningful manpower projections on a continuous basis for planned growth in various fields of technical education system, for meeting the demands of skilled professionals in user agencies. AICTE has so far approved a total number of 563 degree level and 1384 diploma level institutions in the country.

जनजातीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों का विकास

1913. **श्री गोविन्दराम मिरी:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में विशेषकर जनजातीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों के विकास तथा प्रबंध के लिए नये दिशा-निर्देश बनाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत कुछ वर्षों से राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के खेलों के प्रदर्शन का स्तर गिरता जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो सरकार ने खेलों के गिरते हुए स्तर में सुधार लाने के लिए कौन-कौन से प्रभावी कदम उठाए हैं, और

(ङ) क्या सरकार ने खिलाड़ियों में अनुशासन कायम रखने के लिए कोई समिति गठित करने का निर्णय लिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्यक्रम और खेल विभाग) में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक): (क) जी, हां।

(ख) आगामी प्रमुख अंतरराष्ट्रीय चैम्पियनशिप/खेलों में भारत के प्रदर्शन में सुधार करने के उद्देश्य से